भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1877 जिसका उत्तर गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

हलफनामा दाखिल नहीं करने के कारण मामलों में देरी

1877 डा. अशोक बाजपेयी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकार और उसके निगमों की ओर से हलफनामे / उत्तर दाखिल न करने के कारण अक्सर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान में देरी होती है ;
- (ख) क्या सरकार द्वारा नोटिस/कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने की तारीख से इसका जवाब दाखिल करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार की ओर से प्रतिक्रियाएं / शपथपत्र समय पर दायर किए जाएं, कोई निगरानी प्रणाली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी, हां । सूचना संकलित की गई है और उपाबंध-क के अनुसार है ।

उपाबंध-क

क्र.सं. मंत्रालय/विभाग का नाम (क) क्या सरकार अवगत है कि न्यायात्य द्वारा मानतों के निपटान में हुआ विलंब, सरकार और इसके निगमों की और से शायध्यत्र और जवाब के न फाइल करने के कारण उच्चतम न्यायात्य और उच्च न्यायात्य और जवाब/शायध्यत्र समय से फाइल किए गए हैं 1. विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्राव्य द्वारा प्रशासित विधिक स्वना प्रबंधन और आधीन ग्रणाली. एलाआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिक्स पोर्टल के अधीन उ नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत हैं । तिम्बस पोर्टल के अधीन उ नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत वर्णयोगकर्ता मंत्रात्य से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यत्न करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायाल्यों के समक्ष लेंबित हैं । 2. कौशल विकास उत्तर किकास उद्यात के अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्याव्य से ऐसा कोई मामला मंत्रात्य के विधिक क्ष्मन ग्राव्य से ऐसा कोई मामला मंत्राल्य के संज्ञान में नहीं आया है कुछ नहीं न्यायाल्यी मामलों की मॉनीटरी प्राथिक रूपना प्रबंधन से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रात्य मंत्रात्य की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यात्य से ऐसा कोई मामला मंत्रात्य के से एसा कोई मामला मंत्रात्य के से एसा कोई मामला मंत्रात्य के से एसा मंत्रात्य के से एसा कोई मामला मंत्रात्य के से एसा को और से एसा को और से एसा को और से एसा को और से प्रवार के अधीन की ओर से प्रवार के और से एसा को से कार्य को और से प्रवार के से एसा की आप की से से एसा की आप की से से एसा को और से प्रवार के से एसा की आप की से से एसा की से से एसा की अधीन के से एसा को से कार्य के से से एसा की अधीन किस की से एसा की से से एसा की आप की से से एसा की से से एसा की से से एसा की से से एसा की से से से ते ते से से कार के से एसा					७पाषय-पर
में हुआ विलंब, सरकार और इसके निगमों की ओर से श्रायपत्र और जाब के न फाइल करने के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा होती है 1. विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय हुए जाती है कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय हुए हुए जाती है कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय हुए हुए जाती है के श्रीय प्रमासित विविक सूचना प्रवंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिम्बर पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता मंत्रालय ही जुड़ उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लीवत हैं । 2. कौशल विकास और कुछ नहीं कुछ नहीं न्यायालयों मानलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रवंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस)) पोर्टल के माध्यम से ती जा रही है। 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय के अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई	क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम			
में हुआ विलंब, सरकार और इसके निगमों की ओर से श्रायपत्र और जाब के न फाइल करने के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा होती है 1. विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय हुए जाती है कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय हुए हुए जाती है कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय हुए हुए जाती है के श्रीय प्रमासित विविक सूचना प्रवंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिम्बर पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता मंत्रालय ही जुड़ उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लीवत हैं । 2. कौशल विकास और कुछ नहीं कुछ नहीं न्यायालयों मानलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रवंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस)) पोर्टल के माध्यम से ती जा रही है। 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय के अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई			न्यायालय द्वारा मामलों के निपटान	सूचना के प्राप्त होने की	यदि कोई हो, यह सुनिश्चित
जवाब के न फाइल करने के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा होती है कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रशासित विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिम्बस पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत हैं । लिम्बस पोर्टल में रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विधिक न्यायालयों के समक्ष लेंबित हैं । न्यायालयों मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के अधीन के साथ लंकित हैं । न्यायालयों मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है ।			में हुआ विलंब, सरकार और इसके	तारीख से जवाब फाइल	करने के लिए कि सरकार की
जवाब के न फाइल करने के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा होती है कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिम्बस पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता पंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विधिक न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं व्यायालयों मान्रालय के विधिक क्षाया ना मान्ता की मानिटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विधान प्रणाली (एलआईएमबीएम), विधि और न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं व्यायालयों मान्रालय के विधिक सूचना प्रवंधन के के अधीन के समक्ष लंबित हैं व्यायालयों मान्रालय के विधिक सूचना प्रवंधन के विधिक सूचना प्रवंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है विधिक सूचना प्रवंधन और मानीटरिंग (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है			निगमों की ओर से शपथपत्र और	करने तक सरकार द्वारा	ओर से जवाब/शपथपत्र समय
कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हारा होती है कुछ नहीं कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रशासित विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिम्बस पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत हैं । लिम्बस पोर्टल में रिजस्ट्रीकृत ते प्रपोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । कुछ नहीं किया से की जा रही है । किया से की जा रही है । किया से से की की की ले से से से की जा रही है । किया से से की की से			जवाब के न फाइल करने के		से फाइल किए गए हैं
उच्च न्यायालय द्वारा होती है कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रशासित विधिक सूचना प्रबंधन और प्रशासित विधिक सूचना प्रबंधन और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत हैं । लिम्बस पोर्टल में रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । 2. कौशल विकास और उद्यामशीलता मंत्रालय कुछ नहीं व्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई कुछ नहीं विधिक सूचना और मानीटरिंग (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग					, , ,
1. विदेश मंत्रालय कुछ नहीं यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रशासित विधिक स्वना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिग्बस पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रंजिस्ट्रीकृत हैं । लिग्बस पोर्टल में रंजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लीवत हैं । 2. कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं न्यायालयों मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई कुछ नहीं विधिक सूचना और मानीटरिंग (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग					
मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रशासित विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिम्ब्स पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत डिप्योगकर्ता रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विधिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । 2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अछनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई	1.	विदेश मंत्रालय	कुछ नहीं		यह प्रस्तत किया जाता है कि विदेश
प्रशासित विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिम्बस पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत हैं । लिम्बस पोर्टल में रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । 2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं जुछ नहीं न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई प्रशासित विधिक सूचना प्रबंधन और लिम्बस से की जा रही है । विधिक सूचना और मानीटरिंग (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग		• 1			मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा
जीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के साथ जुड़ा है और लिम्बस पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत हैं । लिम्बस पोर्टल में रिजस्ट्रीकृत हैं । लिम्बस पोर्टल में रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । 2. कौशल विकास और कुछ नहीं कुछ नहीं न्यायालयों ने समक्ष लंबित हैं । उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं न्यायालयों के प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय के अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई					प्रशासित विधिक सचना प्रबंधन और
के साथ जुड़ा है और लिम्बस पोर्टल के अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत हैं। लिम्बस पोर्टल में रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं। 2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई किसाथ जुड़ा है और लिम्बस पोर्टल के अधीन करने पार्टल में राजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं। -यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथिमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी कुछ नहीं विधिक सूचना और मानीटरिंग (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग					ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस)
अधीन 3 नोडल अधिकारी और 22 उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत हैं । लिम्बस पोर्टल में रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । 2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं जुछ नहीं न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई					के साथ जुड़ा है और लिम्बस पोर्टल के
उपयोगकर्ता रिजस्ट्रीकृत हैं । लिम्बस पोर्टल में रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । 2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं जुछ नहीं न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई					
पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । 2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कैशाल विकास और कुछ नहीं उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं					
मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज करने/अद्यंतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई					पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता
करने/अद्यतन करने का कार्य करते हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं 2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं जुछ नहीं ज्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई विधिक सूचना और मानीटरिंग (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग					मंत्रालय से जुड़े उन मामलों को दर्ज
हैं, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं । 2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं कुछ नहीं न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई					करने/अद्यतन करने का कार्य करते
कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय और उद्यमशीलता मंत्रालय कुछ नहीं न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथिमक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई कुछ नहीं न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी प्राथिम प्राथिम प्रविधि कार्य विधि कार्य विधिक सूचना और मानीटरिंग (एलआईएमबीएस)					
उद्यमशीलता मंत्रालय प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई प्राथमिक रूप से विधि कार्य विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) विधिक सूचना और मानीटरिंग (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग					समक्ष लंबित हैं ।
उद्यमशीलता मंत्रालय प्राथिमक रूप से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई प्राथिमक रूप से विधि कार्य विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) विधिक सूचना और मानीटरिंग भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई	2.	कौशल विकास और	कुछ नहीं	कुछ नहीं	न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी
स्वना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी कुछ नहीं विधिक सूचना और मानीटरिंग भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग		उद्यमशीलता मंत्रालय			प्राथमिक रूप से विधि कार्य विभाग,
(एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है । 3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी कुछ नहीं विधिक सूचना और मानीटरिंग भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग					विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक
उ. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी कुछ नहीं कुछ नहीं विधिक सूचना और मानीटिरंग (एलआईएमबीएस) मानीटिरंग					सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली
उ. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी कुछ नहीं कुछ नहीं विधिक सूचना और मानीटिरंग (एलआईएमबीएस) मानीटिरंग					(एलआईएमबीएस) पोर्टल के माध्यम
3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्रालय की अधिकारिता के अधीन किसी कुछ नहीं विधिक सूचना और मानीटरिंग भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई (एलआईएमबीएस) मानीटरिंग					
भी अधीनस्थ कार्यालय से ऐसा कोई	3.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय		कुछ नहीं	विधिक सूचना और मानीटरिंग
मामला मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आया है प्रणाली है, जो सरकार की ओर से					(एलआईएमबीएस) मानीटरिंग
			मामला मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आया है		प्रणाली है, जो सरकार की ओर से

		1		जवाबों/शपथपत्रों को समय से फाइल
		``		करने को सुनिश्चित करती है ।
4.	गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक	सार्वजनिक् उद्यम विभाग इस संबंध में	सार्वजनिक उद्यम् विभाग इस संबंध	सार्वजनिक उद्यम विभाग इस संबंध में
	उद्यम विभाग	सरकार् के मौजूदा निदेशों का पालन		सरकार् के मौजूदा निदेशों का पालन
		करता है ।	पालन करता है ।	करता है ।
6.	ज्ल शक्ति मंत्रालय, पेयजल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	और स्वच्छता विभाग			
7.	कौशल विकास और उद्यम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	न्यायालयी मामलों की मॉनीटरी मुख्य
	मंत्रालय			रूप से विधिक सूचना प्रबंधन और
				ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस)
				पोर्टल के माध्यम से की जा रही है ।
8.	रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैनिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कल्याण विभाग		9	
9.	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	वित्तीय सेवा विभाग ने इन न्यायालयी
	विभाग		9	मामलों में प्राप्त न्यायालयी मामलों की
				मॉनीटरी के लिए मानीटर सेल के लिए
				विधिक मानीटरिंग सेल की स्थापना
				की है, जिसकी नियमित अंतराल पर
				ज्येष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की
				जाती है ।
10.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान	3 - 121	3 0 101	3 5 161
	विभाग			
11.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12.	पर्यावरण, वन और जलवायु			विधि और न्याय मंत्रालय (एमओएल
	परिवर्तन मंत्रालय			एंड जे) द्वारा डिजाइन और विकसित
	11 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		की एक अग्रिम प्रति प्राप्त होने पर	
				प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल का
			אייא איי איי איי איי איי איי	7-11(11 (7(1×1)2/1)41(1)) 11(1) 4/1

			शपथपत्र के साथ फाइल करने पर	उपयोग न्यायालयी मामलों की	
				मानीटरिंग के लिए किया जाता है।	
				इसके अतिरिक्त, जिन मामलों	
			इसक आतारक्त, याद मामल म	इसक आतारक्त, जिन मामला	
				में 2 सप्ताह्र के भीतर शपथ पत्र	
				दाखिल नहीं किया जाता है, उनकी	
			शपथपत्र माननीय न्यायालय द्वारा	मानीटरी संयुक्त सचिव के स्तर पर	
			दी गई समय सीमा को ध्यान में	की जाती है ।	
			रखते हुए फाइल किया जाएगा ।		
13.	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	सीईए से संबंधित न्यायालयी मामलों में, उच्चतम न्यायालय और/या उच्च न्यायालयों में शपथपत्रों को भरने में कोई देरी या			
		लंबितता नहीं है और सभी शपथपत्रों को	निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइल	किया गया है । न्यायालयी मामलों की	
		नियमित मानीटरिंग के लिए, सीईए विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल, उच्चतम			
		न्यायालय, उच्च न्यायालयों, ई- न्यायालय आदि की वेबसाइट का उपयोग करता है ।			
14.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		लिम्बस पोर्टल पर न्यायालयी मामले	
	मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा	3 - 10		की स्थिति प्रदर्शित की जाती है और	
	महानिदेशक			जब भी न्यायालय द्वारा सुनवाई की	
				अगली तारीख अधिसूचित की जाती है	
				तो स्थिति को अपडेट किया जाता है	
				1	
15.	भारी उद्योग और सार्वजनिक	इस मंत्रालय से संबंधित माननीय उच्चतम	जावाद के जावादा है।	ी गामलों के शाश्राम ज्वाब निर्धारित	
13.	उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग	जाम भीता के भीता महत्त्वा की ओर में प	गरावाराय/उच्च ग्वायाराय के ग्वायाराय गरल किए जाने हैं । हन गाएलों को वि	धिक सन्तरा पर राषप्यत्र/ जवाब निवासी	
	विभाग	समय सीमा के भीतर सरकार की ओर से फाइल किए जाते हैं । इन मामलों को विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) पोर्टल/आंतरिक प्रणाली पर समय-समय पर अद्यतन और मॉनिटर किया जाता है ।			
16					
16.	नागर विमानन मंत्रालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	एमओएलजे द्वारा विकसित विधिक	
				सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली	
				(एलआईएम बीएस) है, जिसमें	
				एमओसीए, इसके अधीनस्थ संगठन	
				और स्वायत्त निकाय न्यायालयी	
				मामलों से संबंधित डेटा को लगातार	
				अपलोड/अपडेट करते हैं ।	